



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2017/माघ 11, 1938

No. 37]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2017/MAGHA 11, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 18 जनवरी, 2017

सं.टीएएमपी/73/2016-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, कोलकाता पत्तन न्यास(केओपीटी) के कोलकाता डॉक प्रणाली (केडीएस) पर प्रहस्ति ड्राई ब्ल्क कार्गो के लिए, प्रोत्साहन और अर्थदंड के आधार पर संलग्न आदेशानुसार निष्पादन मानक अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/73/2016-केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

(i) श्री टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य(वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जनवरी 2017 के चौथे दिन पारित)

यह मामला, कोलकाता डॉक प्रणाली (केडीएस) पर प्रहस्ति ड्राई ब्ल्क कार्गो के लिए प्रोत्साहन और अर्थ-दंड के आधार पर कार्य निष्पादन मानकों के अनुमोदन के लिए कोलकाता पत्तन न्यास केओपीटी से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 16 जून 2016 के अपने पत्र के अंतर्गत महापत्तन न्यासों के लिए ड्राई बल्क कार्गो हेतु बर्थिंग नीति अप्रेषित की है तथा तदनुसार वास्तविक प्रोत्साहन देने और अर्थ-दंड कार्यान्वित करने के लिए सभी महापत्तन न्यासों को निदेश दिए हैं।

3.1 तदनुसार केपीटी ने दिनांक 26 सितंबर 2016 के अपने पत्र के माध्यम से केडीएस पर प्रहस्तित बर्थिंग ड्राई बल्क कार्गो के प्रहस्तन के बारे में प्रोत्साहन/अर्थदंड के आधार पर कार्य निष्पादन मानक के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

3.2 कथित प्रस्ताव पर संबंधित अपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों के साथ परामर्श किया गया। इस मामले में केओपीटी के परिसर में 24 नवंबर 2016 को एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया और संबंधित उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों ने अपने-अपने विचार रखे।

3.3. मामले पर एकत्रित समग्र सूचना के संदर्भ में मामले में कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने केओपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का निपटान करते हुए एक सकारण आदेश (स्पीकिंग आर्डर) जारी किया है जिसमें केडीएस पर प्रहस्तित ड्राई बल्क कार्गो के लिए प्रोत्साहन/अर्थ दंड के आधार पर कार्य निष्पादन मानक और एंकरेज प्रभारों का अनुमोदन किया गया है।

4.1 प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया स्पीकिंग आदेश, भारत के राजपत्र में अधिसूचना के अंतर्गत प्रकाशनाधीन है जिसमें कुछ समय लग सकता है। इसलिए यह प्राधिकरण, केडीएस पर प्रहस्तित ड्राई बल्क कार्गो के बारे में कार्य निष्पादन मानक, प्रोत्साहन/अर्थ-दंड एंकरेज प्रभार, स्पीकिंग आदेश के अधिसूचित होने की प्रतीक्षा किए बिना लागू कर दी जाएं। अतः, यह प्राधिकरण कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन/अर्थदंड और एंकरेज प्रभार अधिसूचित करता है जो अनुलग्नक के तौर पर संलग्न है।

4.2. केओपीटी के प्रस्ताव अनुसार, यह प्राधिकरण, प्रति पोत क्रेन/डैरिक का न्यूनतम वर्थ निष्पादन मानक प्रति दिन, 01 सितंबर 2016 से लागू माना जाता है। ये प्रोत्साहन/अर्थदंड इस आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से 30 दिन के पश्चात प्रभावी हो जाएंगे तथा आदेश के अधिसूचित होने की तिथि से 1 वर्ष तक वैध रहेंगे।

4.3. इस प्राधिकरण द्वारा पारित सकारण आदेश (स्पीकिंग आर्डर) प्रथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा तथा केओपीटी को संप्रेषित कर दिया जाएगा तथा संबंधित उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों और उपयोक्ता संगठनों को संप्रेषित कर दिया जाएगा।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य(वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./400/16]

अनुलग्नक

कोलकाता पत्तन न्यास

(i) कोलकाता डॉक प्रणाली पर कोयला तथा औद्योगिक नमक वहन करने वाले पोतों के लिए प्रोत्साहन और अर्थदंडों पर आधारित कार्य निष्पादन मानक :-

प्रति पोतीय क्रेन/डैरिक प्रति दिन न्यूनतम वर्थ निष्पादन

वस्तु	मानक (टनों में)
कोयला(इसमें सभी प्रकार का कोयला और कोक शामिल हैं)	1500
औद्योगिक नमक	1400

लक्षित कार्य निष्पादन मानक प्राप्त करने पर दिए जाने वाले प्रोत्साहनों और लक्ष्यों से पिछ़ड़ने पर अर्थदंडों की शर्तें इस प्रकार हैं:

(क) पोत के वर्थ में आगमन के लिए अवधि, विशेष वस्तु के निष्पादन मानक और पोत के पार्सल आकार के आधार पर गणित की जाएगी।

(ख) यदि कोई पोत निर्धारित समय से अधिकाधिक 5 प्रतिशत से कम समय के रुकता है तो उस वस्तु के लिए कोई प्रभार या प्रोत्साहन लागू नहीं होगा।

(ग) 5 प्रतिशत से अधिक समय अवधि के लिए रुकने के मामलों में वर्थ में अतिरिक्त अवधि के लिए रुकने हेतु, वर्थ किराया का दो गुणा प्रभार लिया जाएगा।

(घ) ऐसे मामलों में जहां ठहराव निर्धारित समय से भी अधिक कम है तो अतिरिक्त बचत समय (घंटों) के लिए, 1 x वर्थ किराया का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(ङ) पोत द्वारा प्राप्त वास्तविक कार्यनिष्पादन मानकों की गणना के लिए पोत से संबंधित मौसम से संबंधित कारणों से कार्य में रुकावट को नहीं गिना जाएगा। ऐसे कारणों का विवरण नीचे दिया जाता है:-

- पत्तन में कार्य न होना/पत्तन के उपकरणों की अनुपलब्धता।
- मौसम संबंधी रुकावट।
- पत्तन के कारण पोतों की वर्थ में अदला बदली।
- पोत के नौचालन के लिए तैयार होने के पश्चात पत्तन के कारण विलंब। अर्थात पॉयलट/टग की अनुपलब्धता, ज्वार-भाटा की स्थिति।
- पोतों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ड्राफट सर्वेक्षण के लिए प्रतिपक्ष अधिकतम 30 मिनट का एमस अनुमत किया जाएगा। अतिरिक्त समय लगने की अवधि वर्थ पड़ाव में गिनी जाएगी। बहु पक्षीय सामान के मामलों में एक संज्ञावेक्षक नियुक्त किया जाएगा ताकि अन्तरिम ड्राफट सर्वेक्षणों में बेकार जाने वाले समय को कम किया जा सके। पोतों के एजेंट/आयातक पत्तन के साथ सहयोग करेंगे तथा पत्तन को सूचित करते रहेंगे।
- किसी अन्य कारण से पोत के रुकने की अवधि कार्य निष्पादन मानकों के लिए गणन से बाहर नहीं रखी जाएगी।

(छ) केडीएस पर आने वाले पोतों पर एचडीसी अनुसूची के खंड 2 पर निर्धारित हल्दिया डॉक कंपलेक्स (एचडीसी) पर आने वाले पोतों के संबंध में एंकरेज प्रभार लागू होगा।

(ii) प्रति पोतीय क्रेन/डेरिक प्रतिदिन न्यूनम वर्थ-निष्पादन 01 सितंबर 2016 से प्रभावी माना गया है। प्रोत्साहन और अर्थदंड भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना होने की तिथि से 30 दिन पश्चात प्रभावी हो जाएंगे।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th January, 2017

No. TAMP/73/2016-KOPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48 & 50 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the Performance Norms based Incentive and Penalty in respect of Dry Bulk Cargo handled at Kolkata Dock System (KDS), of the Kolkata Port Trust (KOPT) as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/73/2016 - KOPT

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 4th day of January 2017)

This case relates to a proposal received from Kolkata Port Trust (KOPT) for approving the Performance Norms based Incentive and Penalty in respect of Dry Bulk Cargo handled at Kolkata Dock System (KDS).

2. The Ministry of Shipping (MOS) under cover of its letter dated 16 June 2016 has forwarded the Berthing Policy for Dry Bulk Cargo for Major Ports, 2016 and have directed all the Major Port Trusts to implement the norms with actual incentives and penalties.

3.1. Accordingly, the KOPT, vide its letter dated 26 September 2016, has filed a proposal for approving the Performance Norms based Incentive/Penalty and Anchorage charges in respect of Dry Bulk Cargo handled at KDS.

3.2. The said proposal was taken up for consultation with the concerned users/user organisations of the KOPT. A joint hearing in this case was held on 24 November 2016 at the premises of KOPT. At the joint hearing, the KOPT and the concerned users/organisation bodies have made their submissions.

3.3. With reference to the totality of information collected during the processing of the case, this Authority has passed a speaking Order disposing of the proposal filed by the KOPT for approving the Performance Norms based Incentive/Penalty and Anchorage charges in respect of Dry Bulk Cargo handled at KDS.

4.1. The speaking Order passed by this Authority is in the process of notification in the Gazette of India which is likely to take some time for notification. This Authority desires that the norms for Performance, Incentive/Penalty, Anchorage charges in respect of Dry Bulk Cargo handled at KDS may come into force without waiting for notification of the speaking Order. Therefore, this Authority notifies the Performance Norms based Incentive/Penalty and Anchorage charges in respect of Dry Bulk Cargo handled at KDS, which is attached as **Annex**.

4.2. The Minimum Berth output per ship crane/derrick per day is deemed to have come into effect from 01 September 2016, as proposed by the KOPT. The levy of incentives and penalties would come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of this Order in the Gazette of India and shall remain valid for a period of one year from the date of notification of this Order.

4.3. The speaking Order passed by this Authority will be notified separately and communicated to the KOPT and the relevant users/user organisations in due course of time.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4.Exty./400/16]

Annex**Kolkata Port Trust**

- (i) **“Performance Norms based Incentives and Penalties for ships carrying Coal and Industrial Salt at Kolkata Dock System:-**

Minimum Berth output per ship crane/derrick per day

Commodities	Norms (in tonnes)
Coal (includes all types of coal and cokes)	1500
Industrial salt	1400

Conditionalities for grant of incentives for achievement of Performance Norms and levy of Penalties for non achievement of Performance Norms are as given below:

- (a) For each arrival, ship Berth stay will be calculated based on commodity specific productivity norms and parcel size of vessel.
- (b) If a ship stays within 5% (higher or lower) of the stipulated time for that commodity, then no penalty/incentive will be levied/paid.
- (c) In case where actual Berth stay is more than 5% higher than the stipulated time, the number of additional hours spent at berth will be penalized by 2 x berth hire.

- (d) In case where actual berth stay is more than 5% lower than the stipulated time, number of additional hours saved will be incentivized at 1 x berth hire.
- (e) In computing actual performance achieved by each ship for the purpose of calculating penalty/incentive, any stoppage of operation on account of port related or weather related issues will be discounted. Such exclusions will be limited to:
 - (i) Break down/non availability of port provided equipment at berth.
 - (ii) Weather related stoppages
 - (iii) Shifting of ships between berths on account of port.
 - (iv) Any delays in sailing after vessel readiness to sail on account of port i.e. pilot/tug unavailability, tidal conditions.
 - (v) Draft surveys within the prescribed norms for ships. As a guideline, maximum 30 mins per party for interim draft survey would be allowed.

Any additional time incurred in draft surveys will be considered in berth stay. Where practicable, in case of multi-party consignment, common surveyors are to be appointed so as to reduce time lost during interim draft surveys. Vessel Agent/Importers must co-ordinate and inform port.

- (vi) Any stoppages because of other reasons are not to be excluded for calculation of performance norms, unless specifically approved by Board.”

- (f) The levy of anchorage charges in respect of vessels visiting Haldia Dock Complex (HDC) prescribed at Clause 2 of the HDC schedule will apply in respect of vessels visiting KDS.

(ii) The Minimum Berth output per ship crane/derrick per day is deemed to have come into effect from 01 September 2016. The levy of incentives and penalties will come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India.
